1750. [Transferred to 19th March 1993.]

Increasing Pollution of Bangalore

1751. SHRI J. P. JAVALI : Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that air pollution in cities is increasing year by year and Bangalore is identified as the third most polluted city in the country;

(b) which are the other cities in Karnataka, with five lakhs and above population, which are facing this problem; and

(c) what are the cause of air pollution and what steps are being considered to control the same ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRIMATI MARGARET ALVA) : (a) While the level of air pollution in Bangalore city is increasing, the levels of pollutants such as sulphur dioxide, Oxide of Nitrogen and suspended particulate matter are well within the permissible limits. Bangalore is not the third most polluted city in the country.

(b) Hubli-Dharwad and Mysore face similar air Pollution problems.

(c) The causes for the air pollution are industrial emissions, Vehicular emissions and refuse incineration. The provision of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 provided for pollution control and abatement of air pollution. The State Government has drawn up a Scheme costing Rs. 1.75 crores for checking air pollution in Bangalore. A public awareness programme has also been launched by the State Government. Since the major contribution to air pollution is from vehicular emissions, the Police and the Transport Departments in the State with the help of State Pollution Control Board have checked 5671 vehicles in Bangalore city, during 1991-92 and 1992-93 of which, 1129 violators have been notified and cases filed in the court.

Coastal Zone Management Plans

1752. SHRI SHIV PRATAP MISHRA : Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state :

(a) whether the task force set up by Government's in November, 1992 for examining the draft coastal zone management plans for all coastal States and Union territories has submitted its report;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the time by when it is likely to submit its report ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRIMATI MARGARET ALVA) : (a) and (b) No Sir. The Task Force has been set up to examine and finalise the draft Coastal Zone Management Plans being submitted by Coastal States/UT Administrations. No report is expected from it.

(c) The Plans are examined by the Task Force as and when they are submitted by the State Governments/UT Administrations.

प्रत्येक राज्य में वनाच्छादित क्षेत्र की प्रतिशतता

1753. **श्री रामजी लाल** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में इस समय वनाच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत कितना-कितना है और दो वर्ष पूर्व यह प्रतिशत कितना-कितना था;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वनाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय सरकार के द्वारा प्रत्येक राज्य को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1993-94 के दौरान आवंटित की जाने वाली प्रस्तावित वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) 1985-87 और 1987-89 की अवधियों

से संबंधित उपग्रह प्रतिबिम्बिकी की दृश्य व्याख्या के आधार पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा किये गये मूल्यांकन के अनुसार वन क्षेत्रों की प्रतिशतता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वनरोपण/वृक्षारोपण गतिविधियों के लिये प्रदान की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) वर्ष 1993–94 के लिये 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वनरोपण/वृक्षारोपण के लिये निधियों के राज्यवार आवंटन को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण –I

1985–87 और 1987–89 की प्रतिबिम्बकी के आधार पर मूल्यांकित वास्तविक वन क्षेत्र की राज्यवार प्रतिशतता

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1985–87 प्रतिबिम्बिकियों के आधार पर मूल्यांकित वास्तविक वन क्षेत्र की प्रतिशतता	1987–89 प्रतिबिम्बिकियों के आधार पर मूल्यांकित वास्तविक वन क्षेत्र का प्रतिशत
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	17.31	17.2
2.	अरुणाचल प्रदेश	82.3	82.1
3.	असम	33.2	31.6
4.	बिहार	15.49	15.3
5.	गोआ	35.2	33.8
6.	गुजरात	6.0	6.1
7.	हरियाणा	1.3	1.2
8.	हिमाचल प्रदेश	24.03	21.2
9.	जम्मू व कश्मीर	9.1	9.0
10.	कर्नाटक	16.74	16.8
11.	केरल	26.1	26.5
12.	मध्य प्रदेश	30.1	30.6
13.	महाराष्ट्र	14.32	14.3
14.	मणिपुर	80.0	79.2
15.	मेघालय	69.8	70.8
16.	मिजोरम	86.2	89.4
17.	नागालेण्ड	86.8	86.4
18.	उड़ीसा	30 3	30.3
19.	पंजाब	2.3	2.3
20.	राजस्थान	3.8	3.7
21.	सिक्किम	42.8	42.8

1	2	3	4
22.	तमिलनाडु	13.62	13.6
23.	त्रिपुरा	50.08	52.8
24.	उत्तर प्रदेश	11.5	11.4
25.	पश्चिम बंगाल	9.6	9.0
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	91.96	92.4
27.	चंडीगढ़	7.02	4.4
28.	दादर व नगर हवेली	41.84	42.0
29.	दमन और दीव	1.78	1.8
30.	दिल्ली	1.48	1.5
31.	लक्षद्वीप	—	—
32.	पांडिचेरी	—	—

विवरण–II

20–सूखी कार्यक्रम के अन्तर्गत वनरोपण/वृक्षारोपण के लिए निधियों का राज्य–वार आवंटन :

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाख रुपयों में		
		1990–91	1991–92	1992–93
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	2167.16	2878.00	1327.76
2.	अरुणाचल प्रदेश	518.13	624.64	978.60
3.	असम	1848.77	1848.84	1808.80
4.	बिहार	3621.88	4245.00	2381.21
5.	गोवा	127.62	104 65	168.00
6.	गुजरात	3508.00	5819.69	4126.52
7.	हरियाणा	2389.85	3937.75	2538.25
8.	हिमाचल प्रदेश	2136.86	2754.98	2943.00
9.	जम्मू व कश्मीर	1299.60	1997.00	1383.23
10.	कर्नाटक	2464.67	5577.51	3708.65
11.	केरल	1542.84	1991.50	2230.20
12.	मध्य प्रदेश	4363.07	7031 00	3882.16
13.	महाराष्ट्र	4059.77	5177.87	3425 56
14.	मणिपुर	465.52	491.12	364.00
15.	मेघालय	577.57	1407 37	980.00
16.	मिजोरम	496.71	290.00	प्राप्त नहीं

1	2	3	4	5
17.	नागालैण्ड	444 41	169.27	336.00
18.	उड़ीसा	3617.55	3669.36	3191.85
19.	पंजाब	574.85	944.12	568.40
20.	राजस्थान	4023.02	7703.66	4792.92
21.	सिक्किम	271.36	494.73	344.40
22.	तमिलनाडु	2979.98	1773.69	2841.04
23.	त्रिपुरा	502.44	1326.30	407.40
24.	उत्तर प्रदेश	6680.87	9742.99	5421.51
25.	पश्चिम बंगाल	2409.15	2740.31	1504.80
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	293.16	120.00	350.00
27.	चंडीगढ़	163.92	30.00	प्राप्त नहीं
28.	दादर और नगर हवेली	110.11	93.54	118.83
29.	दिल्ली	176.36	17.00	14.00
30.	दमन और द्वीव	18.75	100.00	199.50
31.	लक्षद्वीप	3.03	8.50	11.20
32.	पांडिचेरी	38.62	88.57	35.00
	योग	53895.60**	75198.96	52382.79*

* इसमें जवाहर रोजगार योजना की 96.00 करोड़ रुपये की निधियां शामिल नहीं है । राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड का 115 करोड़ रुपये का बजट भी शामिल नहीं है । बीस सूत्री कार्यक्रम के सूत्र सं० 16 के लिए कुल अनन्तिम परिव्यय 735.00 करोड़ रुपए है ।

** बजट में राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड को दिए गए 36 करोड़ रूपए शामिल नहीं है। जिन्हें राज्यवार आबंटित नहीं किया गया है ।

प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए तंत्र

1754. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक बहि:स्रावों को प्रदूषण रहित बनाने की प्रक्रिया को विनियमित करने और उस पर निगरानी रखने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी औद्योगिक बहि:स्रावों को नदियों और समुद्र में छोड़ने से पूर्व उपचारित किया जायेगा और उन्हें पूर्णतया प्रदूषण रहित बनाया जाएगा, केन्द्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर कोई तंत्र बनाया गया है; यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है :

(ख) इस तंत्र द्वारा मध्य प्रदेश में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ;

(ग) मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में अभी भी किन-किन स्थानों पर इस प्रकार की समस्या बनी हुई है; और

(घ) बिलासपुर के कोरबा और रायपुर क्षेत्रों में तथा दुर्ग जिले में जल और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?